वैकल्पिक विवाद समाधान और न्याय

सोना खुराना*

भारत के आजाद होते ही भारत के विद्वानों ने विचार किया कि देश को चलाने के लिए नियम और कानून कि आवश्यक्ता होगी और तुरंत ही कानून बनाने की तयारी करदी और नियम कानून का उलंघन करने वाले को दंड और पीडित को न्याय मिले। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य लोगों विद्वानों द्वारा त्यार किए गए भारतिय, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मारत के सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार है और न्याय। सभी का हक है, यह प्रयास किया जाए कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, मत, मजहब का क्यों ना हो।

हमारे भारतीय संविधान के द्वारा न्याय व्यवस्था का सही प्रकार से पालन हो सके, इसके लिए अदालत की व्यवस्था की गई है।

न्याय पाने के भी अनेक तरिके हैं जिस में से एक वार्ता और चर्या के माध्यम से एक अनुकूल समाध्यान पर पहुँचने के द्वारा पक्षों के बीच विवादों और असहमति को हल करने के की एक तकनीक है। यह विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों के अलावा एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास है। वैकल्पिक विवाद समाधान एक विवाद को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है, जो न्यायालयों में मुकदेबाजी के विकल्प हैं। इस प्रकार की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया में, विवादों में शामिल दोनों पक्ष इस व्यक्ति का चयन करते हैं जो सर्वसम्मति से उनके विवादों को सुनेगा और हनका समाधान करेगा। भारत में एडीआर भारत के संविधान के तहत अनुछेद 14[1] और अनुछेदश के आधार पर स्थापित किया गया है।

पर वैकल्पिक विवाद समाधान का इतिहास कैसे हुआ यह शुरू, क्योंकि यह माना जाता है कि वर्तमान न्यायपालिका प्रणाली अत्यंत महंगी और विलंधित है। विवाद के पक्षकारों को न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसी वजह से न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक उपायों को जन्म दिया। वैकल्पिक उपाय सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करता है जिसके कारण विवादित पक्षों द्वारा अपने विवादों को समाधान किया जाता है कर तंत्र को प्राथमिकता भी दी जा रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 लोगों को वह अवसर प्रदान करती है,[2] यदि न्यायलय को लगता है कि अदालत के बाहर समझौते के तत्व मौजूद हैं तो अदालत संभावित निपटान की शर्ते तैयार करती है और ए.डी. आर से निपटने वाले अधिनियम, 1997 (लोक अदालत प्रणाली की स्थापना) मध्यस्यता और सुलह अधिनियम 1996 वैकल्पिक विवाद समाधान को, पंचायत, समझौता, मध्यस्यता, लोक आदालत और वार्ता द्वारा वीत किया जा सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान न्याय प्रणाली को मजबूत करने का बहुत जरूरी हिस्सा है जिसको और महत्वलता ही जानी चाहिए। न्याय प्रणाली पर देशवासियों को यकीन बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए। आधुनिक न्याय प्रणाली आधुनिक माध्यम ।

विकल्प विवाद समाधान (ए.डी.आर.) से संबंधित कई मामले हैं। यहां कुछ प्रमुख मामले हैं:

---

* विधि छात्र, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीस

1 अनुछेद 14, भारत का संविधान

2 नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908

1.सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (2020)[3]

इस मामले में, प्रतियोगी पक्षों के बीच हुए एक समझौते से विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें कॉपर कंसेंट्रेट की बिक्री की गई थी। अपीलेंट ने एक एर्बिट्रेशन क्लॉज का स्वरूप, जिसमें एक दो-स्तरीय एर्बिट्रेशन प्रक्रिया शामिल थी, जारी किया। इस समझौते में उल्लिखित था कि पहले स्तर का एर्बिट्रेशन भारत में संपन्न होगा और फिर पीड़ित पक्ष लंदन में आंतरराष्ट्रीय चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) में अपील कर सकता है। भारत में हुए एर्बिट्रेशन ने शून्य पुरस्कार दिया। इसके बाद, इसे आईसीसी लंदन में अपील किया गया। पुरस्कार को पास करने से पहले ही प्रतिवादी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एर्बिट्रेशन क्लॉज को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के पक्ष में एक अड इंटरिम रोक दिया गया; हालांकि, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एर्बिट्रेशन प्रक्रिया के जारी रखने की अनुमति दी। अंत में, आईसीसी के एर्बिट्रेटर के पक्ष में पुरस्कार पास किया गया। प्रतिविादी ने इसके प्रवर्तन की आपत्ति की।

कई मुकदमों के बाद, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और उठाया गया प्रश्न था, भारत में दो-स्तरीय एर्बिट्रेशन प्रक्रिया की कानूनीता क्या है और क्या आईसीसी की अपील को कानूनी रूप से प्रवर्तित किया जा सकता है?

तीन न्यायाधीशों की बेंच ने यह निर्णय लिया कि भारत के कानून के अनुसार, दो-स्तरीय एर्बिट्रेशन प्रक्रिया स्वीकृत और मान्य है। पक्षों को ऐसे समझौते में प्रवेश करने का स्वतंत्रता है जो गैर-कानूनी अपील प्रदान करता है ताकि अदालत के द्वारा कम हस्तक्षेप हो और वे अदालती प्रक्रिया से बच सकें। प्रतिवादी ने यह दावा किया कि पुरस्कार को एर्बिट्रेशन अधिनियम की धारा 48 के खिलाफ ठहराया गया था, और उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का और मामले की समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। इस प्रकार अदालत ने यह खोजा कि लिब्यून के समक्ष मौजूद होने और उनके समर्थन में उनके साक्षात्कार के लिए आग्रह किए जाने के बावजूद, पुरस्कार पारित करने के समय प्रतिवादी ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस प्रकार, प्रतिवादी पक्ष ने इन अवसरों का उपयोग नहीं किया। इसलिए, अदालत ने यह खोजा कि प्रतिवादी ने समयसीमा का पालन नहीं किया और न्याय के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ गया और उसने यह ठाना कि विदेशी पुरस्कार को भारत में पूर्ति किया जा सकता है।

2. आवितेल पोस्ट स्टुडियोज़ लिमिटेड और अन्य बनाम एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड और अन्य (2020)[4]

इस मामले में, आवितेल और एचएसबीसी ने दो समझौतों में प्रवेश किया, शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट के माध्यम से, जिसके अंतर्गत एचएसबीसी ने आवितेल में 7.80% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया, और शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट ("एसएचए")। उनमें से दोनों में एर्बिट्रेशन[5] की प्रावधान होती थी। इन बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ; एचएसबीसी ने दावा किया कि आवितेल के प्रमोटरों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक लाभकारी समझौते को समाप्त करने के कगार पर हैं, और इसलिए, इसने आवितेल में निवेश किया। हालांकि, एचएसबीसी ने पाया कि ऐसा कोई समझौता नहीं है और एचएसबीसी द्वारा निवेश किए गए 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहले ही आवितेल के प्रमोटरों की हिस्सेदारी

3 सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 2020 SCC Online SC 479

4 आवितेल पोस्ट स्टुडियोज़ लिमिटेड और अन्य बनाम एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड और अन्य, 2020 SCC online SC656

5 एर्बिट्रेशन और सुलह

वाली कंपनियों में बहा दिए गए थे। इस पर, एचएसबीसी ने एर्बिट्रेशन क्लॉज का उपयोग किया, और एक पुरस्कार एचएसबीसी के पक्ष में हुआ जिसमें इसका दावा सही ठहराया गया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। एचएसबीसी ने धारा 9 के तहत एक पिटीशन दाखिल किया, जिसमें वह अमेरिकी डॉलर 60 मिलियन के पूरे दावे राशि के जमा का आदेश मांगा।

पुरस्कार की पूर्ति की आवश्यकता को चुनौती देते हुए, आवितेल ने यह दावा किया कि भारतीय कानून के तहत जारी जुर्म के विषय पर विवाद, जैसे कि जालसाजी और प्रतिनायक, एर्बिट्रेबल नहीं हैं और इसलिए अंत में पुरस्कार अमान्य बना देगा। दूसरी ओर, एचएसबीसी ने यह दावा किया कि गंभीर धाराओं की अपनाई जा सकती है यदि भ्रांति के गंभीर आरोप एर्बिट्रेशन क्लॉज को दूर करेंगे।

इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यह परीक्षण तय किया कि जब भ्रांति का गंभीर आरोप होगा तो अर्बिट्रेबलता का उपयोग कब होगा:

(1) क्या यह याचिका पूरे समझौते और, ऊपर सबसे, एर्बिट्रेशन के समझौते को भी प्रभावित करके उसे अमान्य बना देती है, या

(2) क्या धाराओं का आरोप प्रतिस्थानीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं डालता, जिसमें पक्षों के आंतरिक कार्यों को छूने का प्रयास होता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होता।

यदि मामले इस ऊपर दी गई परीक्षण की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, तो वे एर्बिट्रेबल हैं। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह ठाना कि वर्तमान मामला एक नागरिक मामला है और उसे भारत में पुरस्कार की पूर्ति के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अलग रखने का समर्थन किया।

3.भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड और अन्य (2020)[6]

इस मामले में, भारत सरकार ने केयरन इंडिया लिमिटेड के साथ एक प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट ("पीएससी") करने के लिए प्रवेश किया था (जिसे बाद में वेदांत ने प्राप्त किया) रव्वा गैस और ऑयल फ़ील्ड में पेट्रोलियम संसाधनों का अन्वेषण और विकसन करने के लिए। विवाद पीएससी के तहत उल्लिखित विकास लागत के प्रावधान से उत्पन्न हुआ, जिसमें उत्तराधिकारी को हक है। इस प्रावधान के बारे में बात थी जो आधार विकास लागत की थी। उत्तराधिकारी ने आधार विकास लागत उठाई, जो यात्रात्मक रूप से सीमित किए जाने वाले राशि से अधिक थी। उत्तराधिकारी ने भारत सरकार से यह मांग की कि उन्हें पीएससी के तहत उठाई गई लागत को पुनः प्राप्त करने के लिए सीमा में वृद्धि की जाए।

इस पर, उन्होंने मामले को मलेशियाई ट्रिब्यूनल को संदर्भित किया, और एक पुरस्कार पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि आधार विकास लागत को अदालत द्वारा चुकता किया जाना चाहिए था जिसकी लागत 2000-2009 के अनुबंध के लिए उठाई गई थी। अपील की प्रक्रिया के बाद, मामला अंत में दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा। उत्तराधिकारी ने धारा 47, धारा 49 के साथ, एर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम,[7] 1996 के तहत पूर्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। भारत सरकार ने पुरस्कार की समर्थन को नकारा करते हुए एक आवेदन दाखिल किया जिसमें यह दावा किया गया कि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ था और एर्बिट्रेशन को प्रस्तुत करने के क्षेत्र के बाहर के मामले शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की आपत्तियों

6 भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड और अन्य (2020), SCC online Del 1426

7 एर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम

को खारिज किया और उत्तराधिकारी द्वारा दाखिल की गई देरी के आवेदन को स्वीकृत किया। इसके बाद, हाईकोर्ट ने पुरस्कार को पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया। इस पर, आपीलेन्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आपत्ति दर्ज की।

सुप्रीम कोर्ट ने यह ठाना कि याचिका की पूर्ति समय सीमा के तहत की गई थी जैसा कि 1963 के सीमा अधिनियम की धारा 137 में निर्धारित किया गया था। यदि कोई विलंब हो, तो इसे क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पुरस्कार की गलतियों को धारा 48 के तहत सुधारने या पुरस्कार के योग्यता की समीक्षा करने के लिए न्यायिक अदालत से सहमति नहीं होगी। इस प्रकार, अदालत विदेशी पुरस्कार पर न्यायिक प्रभुत्व का अभ्यास नहीं कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह आपीलकर्ता ने साबित करने में विफल रहा है कि यह न्याय के मौलिक धाराओं के खिलाफ था, क्योंकि पहली बात, यह आपीलकर्ता ने साबित नहीं किया कि उप-प्रक्रियात्मक प्रक्रिया के उल्लंघन की पुष्टि की गई और उसने साबित नहीं किया कि यह भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन कर रहा था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को समर्थन किया।

4. भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम काइजर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक।, (2012)[8]

भातिया इंटरनैशनल और वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट, 1996 के भाग I[9] ने आर्बिट्रेशन अवार्ड के संबंध में प्रक्रियाएँ, पुरस्कृति, अंतरिम सहायता, और अपील की प्रावधानें स्थापित की थीं और कहा था कि इसका अनुप्रयोग सभी भारतीय आर्बिट्रेशनों पर होगा, जब तक पुलक्रित या स्पष्ट सहमति के द्वारा पूरी या किसी भी प्रावधान को बाहर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग I और भाग II के बीच में एक स्पष्ट विभाजन है जो पूरी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं और कोई भी ओवरलैपिंग प्रावधान नहीं हैं।

इस मामले में न्यायालय ने एक 'सीट' और 'वेन्यू' के बीच एक अंतर खींचा। आर्बिट्रेशन समझौता एक विदेशी देश को आर्बिट्रेशन की सीट/स्थान के रूप में नामित करता है और इसे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला कानून चुनता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन की सीट के रूप में दूसरे देश का चयन करना निर्वाचन करता है कि उस देश के आर्बिट्रेशनों के प्रबंधन और निगरानी से संबंधित कानून को प्रक्रियाओं पर लागू होगा। इसलिए, यह समझा जा सकता है कि भाग I केवल उन आर्बिट्रेशनों पर लागू होता है जिनकी सीट/स्थान भारत में है।

न्यायालय ने भातिया इंटरनैशनल केस में की गई टिप्पणियों से असहमति जताई और अधिक धारात्मक रूप से अधिनिर्णय किया कि अधिनिर्णित कृत्य के लॉजिकल निर्माण के आधार पर, जब आर्बिट्रेशन की सीट भारत के बाहर होती है, तब भारतीय न्यायालयों को इंटरिम उपाय प्रदान करने की शक्ति नहीं है। इसलिए, धारा 36 के अंतर्गत धारित पुरस्कृत अवार्ड से पहले के आर्बिट्रल प्रक्रियाएँ केवल उन आर्बिट्रेशनों से संबंधित हो सकती हैं जो भारत में होते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि विदेश संबंधित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन में, भारत में न तो आर्बिट्रेशन द्वारा और न ही किसी याचिका द्वारा आंतरिम सहायता के लिए कोई आवेदन स्वीकृत होगा।

---

8 भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम काइजर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक।, (2012) 9 SCC 552

9 आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट, 1996